

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.....

Dated...26.08.2020.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

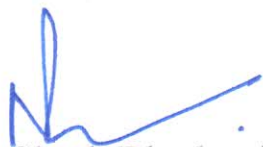
In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF's letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **2.630 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of the जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों-काकड़ीघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से सुनियाकोट कोटली तक मोटर मार्ग (लम्बाई 4.00 कि०मी०) **district Almora falls within jurisdiction Suniyakot, Kotali, Sauni Village (s) in Ranikhet Tahsils.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **2.628** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure to annexure.....
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.:-YES
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.:-YES

Encl: As above


ज.स.सिंह
ज.स.सिंह कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा


Nitin Singh Bhadauria
District Collector, Almora

FORM-II
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.....

Dated... 26-08-2020

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that **2.628 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of Provincial Division P.W.D. Almora for the जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों-काकड़ीघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से सुनियाकोट कोटली तक मोटर मार्ग (लम्बाई 4.00 कि०मी०) **district Almora falls within jurisdiction Suniyakot, Kotali, Sauni Village (s) in Ranikhet Tahsils.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **2.630** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure to annexure
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Suniyakot, Kotali** villages (s) is enclosed as annexure 3.
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- (f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above


 जिला कलकत्ता अधिकारी
 अल्मोड़ा


 Nitin Singh Bhadauria
 District Collector, Almora

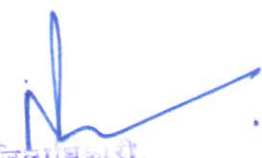
OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT ALMORA (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Nitin singh Bhadauria, I.A.S., deputy commissioner, Almora on date ~~26.08.2020~~.....at time ~~4:00 PM~~.....at Almora in which application claiming rights of Suniyakot, Kotali, Sauni measuring 2.628 hac. for the जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों-काकड़ीघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से सुनियाकोट कोटली तक मोटर मार्ग (लम्बाई 4.00 कि०मी०) of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Ranikhet** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Almora


जिलाधिकारी,
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

DATE:


जिला स्तरीय समिति का सदस्य
अल्मोड़ा

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम:-जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों-काकाड़ीघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से सुनियाकोट-कोटली तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 4.00 कि०मी०

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रानीखेत

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, रानीखेत

उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत विधानसभा अल्मोड़ा में जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों-काकाड़ीघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से सुनियाकोट-कोटली तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 4.00 कि०मी० के निर्माण हेतु शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 1.359 हे० सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि 1.269 है० अर्थात् कुल 2.628 हे० का प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील-रानीखेत) की दिनांक 12.08.2008 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक सु० श्री अमर सिंह उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री अमर सिंह संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत अध्यक्ष

JOINT MAGISTRATE
RANIKHET.

2- श्री अमर सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा सदस्य

3- श्री नरेश जोषी समाज कल्याण अधिकारी रानीखेत सदस्य/सचिव

4- श्री पुष्कर सिंह बी०डी०सी० क्षेत्र जालंधारी सदस्य पुष्कर सिंह कनिष्ठ उप प्रमुख

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों-काकाड़ीघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से सुनियाकोट-कोटली तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 4.00 कि०मी० के निर्माण हेतु शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 1.359 हे० सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि 1.269 है० अर्थात् कुल 2.628 हे० वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी

अमर सिंह
विभागीय समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड रानीखेत
जनपद अल्मोड़ा

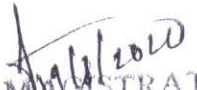
(10)

दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों-काकाड़ीघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से सुनियाकोट-कोटली तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 4.00 कि०मी० के निर्माण हेतु शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 1.359 हे० सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि 1.269 हे० अर्थात् कुल 2.628 हे० प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


JOINT MAGISTRATE
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-रानीखेत
जनपद-अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


JOINT MAGISTRATE
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-रानीखेत
जनपद-अल्मोड़ा

परियोजना का नाम:-जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों-काकाड़ीघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से सुनियाकोट-कोटली तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 4.00 कि०मी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- (सुनियाकोट)

तहसील व जिला-रानीखेत, अल्मोड़ा

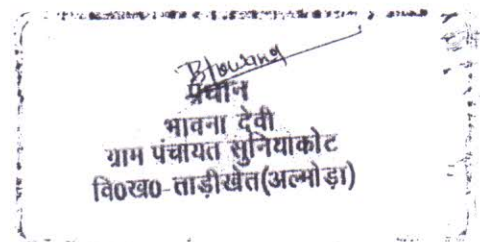
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों-काकाड़ीघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से सुनियाकोट-कोटली तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 2.628 है० वन भूमि, का प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत (सुनियाकोट) द्वारा दिनांक 24.02.2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सुनियाकोट के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान

Signature



परियोजना का नाम:-जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों-काकाड़ीघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से सुनियाकोट-कोटली तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 4.00 कि०मी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम-सुनियाकोट

तहसील व जिला-रानीखेत, अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों-काकाड़ीघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से सुनियाकोट-कोटली तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 2.628 है० वन भूमि, का प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत, सुनियाकोट द्वारा दिनांक 14.02.2008 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कोटली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

केवलराम

सरपंच,

वन पंचायत कोटली

पट्टी कन्धारखुर्वा

तहसील रानीखेत जिला अल्मोड़ा

जिला अधिकारी

अल्मोड़ा

दिनांक 14.02.2008

ग्राम प्रधान

प्रधान

गावना देवी

ग्राम पंचायत सुनियाकोट

वि०ख०-ताड़ीखेत(अल्मोड़ा)

दिनांक 24.02.2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत कोटुली

क्रम सं०	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	केवल राम	केवल राम
2	बेची राम	Bachi Ram
3	शामेन्द लाल	Shameend Lal
4	गोपाल राम	Gopal Ram
5	शेर सिंह	शेर सिंह
6	नारामण सिंह	नारामण सिंह
7	पुरन सिंह	पुरन सिंह
8	राहुल सिंह	राहुल सिंह
9	पंकज पश्राद	Pankaj Pashra
10	शामेन्द पश्राद	शामेन्द सिंह
11	कमला देवी	कमला देवी
12	रेवती देवी	रेवती देवी
13	हेमा देवी	हेमा देवी
14	गंगा देवी	गंगा देवी
15	पुष्पा विष्णु	पुष्पा विष्णु

ग्राम प्रधान
~~Bhawan~~
प्रधान
भावना देवी
ग्राम पंचायत सुनियाकोट
वि०ख०-ताड़ीखेत(अल्मोड़ा)

परियोजना का नाम:-जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों-काकाड़ीघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से सुनियाकोट-कोटली तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 4.00 कि०मी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम-

सुनियाकोट

तहसील व जिला-रानीखेत, अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों-काकाड़ीघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से सुनियाकोट-कोटली तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 2.628 है० वन भूमि, का प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत (सुनियाकोट) द्वारा दिनांक 24.02.2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सौनी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान

सुरपंच

वन पंचायत सौनी,
पो० ग्रो० - सूरु,
नदटी-कन्दार खुवा (अल्मोड़ा)

प्रधान
भावना देवी
ग्राम पंचायत सुनियाकोट
वि०ख०-ताड़ीखेत(अल्मोड़ा)

दिनांक 24.02.2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत सौनी

क्रम सं०	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	सुनील सिंह	सुनील सिंह
2	पिंजरा सिंह	पिंजरा सिंह
3	तारक सिंह परहर	तारक सिंह
4	राकेश सिंह	राकेश सिंह
5	रमेश सिंह	रमेश सिंह
6	कुशाल सिंह	कुशाल सिंह
7	लाल सिंह	Lal Singh
8	चानंद सिंह	Chander Singh
9	मोहनी देवी	मोहनी देवी
10	लीला देवी	लीला देवी

ग्राम प्रधान

Bhawanra

प्रधान

भावना देवी

गावना देवा
ग्राम पंचायत सुनियाकोट
वि०ख०-ताड़ीखेत(अल्मोड़ा)